

## पैक्स कार्यक्रम

### परिचय

पैक्स एक कार्यक्रम के रूप में ऐसी पहल है जो ब्रिटेन (यूनाइटेड किंगडम) सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) की नागरिक समाज के साथ की गई भागीदारी है। पैक्स सामाजिक वंचित समुदायों को प्रभावी रूप से उनके अधिकारों और पात्रताओं की दावेदारी पाने में मदद करता है।

सामाजिक वंचित समूहों में शामिल हैं—

- अनुसूचित जातियाँ
- अनुसूचित जनजातियाँ
- मुस्लिम
- महिलायें और लड़कियाँ
- विकलांग व्यक्ति

यह पंचवर्षीय कार्यक्रम (2009–2014) का उद्देश्य है। नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) का स्थानीय, जिला और राज्य स्तरीय नीतियों, कार्यक्रमों और संस्थानों को बढ़ावा देने में समर्थन करना। यह मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, जल और स्वच्छता के क्षेत्रों में ध्यान देता है। पैक्स (2009–2014) 7 राज्यों उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 90 जिलों में लागू किया जायेगा।

पैक्स का समग्र उद्देश्य है। सामान्य जनसंख्या और सामाजिक वंचित/अपवर्जित जनसंख्या के बीच सामाजिक कल्याण के फसाले को कम करना।

इसका विशिष्ट प्रायोजन है 90 जिलों में 80 लाख सामाजिक वंचित परिवारों को मिलने वाले सामाजिक पात्रताओं को पाने में सुधार लाना।

वृहद लक्ष्य और उद्देश्य के अन्तर्गत निम्न चार स्पष्ट परिणाम दिये गये हैं—

1. सुदृढ़ सीएसओ पैक्स के लक्षित क्षेत्रों में महिलाओं और सामाजिक वंचित समुदायों से जुड़े मुद्दों को उठाये और प्राथमिकता दी गई।
2. सामाजिक वंचित समूहों का बेहतर प्रतिनिधित्व और ग्रामीण/ ब्लॉक/ जिला/ राज्य स्तर की, सरकारी निर्णय लेने वाले निकायों की और सीएसओ स्तर पर बनी समीतियों में उनका कहा अधिक माना गया।
3. सेवा प्रदाताओं को सामाजिक वंचित लोगों के प्रति और अधिक जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाने में नागरिक समाज द्वारा कार्य किया गया।
4. कार्यक्रम से प्राप्त सीखों को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जिले में पैक्स कार्यक्रम का क्रियान्वयन पेस संस्था तीन पार्टनर संस्थाओं — जे.एस.एस., प्रसार, अहेड संस्थाओं के साथ प्रतापगढ़ के चार ब्लॉक सांगीपुर, रामपुर, संग्रामगढ़, लक्ष्मणपुर, संडवा चन्द्रिका व कौशाम्बी के एक ब्लॉक करर्मा में कर रही है।